1	2	3	4	5	6	7	8
8.	राजस्थान	19.14.	24.37	24.32	24.91	29.85	31.86
9.	हरियाणा	99.05	114.39	104.01	114.78	121.71	123.68
10.	हिमाचल प्रदेश	35.16	34.37	31.45	29.41	30.03	30.50
11.	जम्मु और कश्मीर	39.96	44.44	41.35	39.41	43.12	47.50
12.	पंजाब	159.67	165.56	158.81	158.83	170.16	167.28
13.	उत्तर प्रदेश	87.95	88.94	84.88	89.25	96.58	101.45
14.	बिहार	57.08	59.49	63.68	62.56	69.79	76.96
15.	उडीसा	20.08	19.97	21.55	22.06	23.36	25.23
16.	पश्चिम बंगाल	86.93	87.18	85.63	87.25	88.24	99.26
17.	अरुणाचल प्रदेश	1.79	1.86	1.96	2.27	2.17	1.53
18.	असम	9.92	9.20	6.91	8.70	9.65	12.81
19.	त्रिपुरा	19.96	23.32	20.15	17.76	17.35	19.07
20.	मणिपुर	40.87	45.98	48.98	48.69	45.74	63.22
21.	मेघालय	11.03	13.90	12.49	13.43	13.51	11.72
22.	नागालैंड	5.30	3.29	3.25	4.77	2.83	2.29
23.	मिजोरम	9.20	8.33	11.75	9.23	9.21	7.62
24	सिक्किम	10.11	11.79	8.77	7.90	6.20	8.40
	अखिल भारत	67.48	69.84	65.53	66.67	73.12	74.81

छोटे किसानों की कृषि परियोजनाओ को बढ़ावा देने हेतु योजना

2890. **श्रीमति आंनदी ज. पटेल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे किसानों की कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) छोटे किसानों को इस योजना के माध्यम से किस प्रकार के लाभ मिलेंगे; और

(घ) क्या उक्त योजना को लागू कर दिया गया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) जी हां। वर्ष 1992-93 में केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में, सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 18 जनवरी, 1994 के स्बायत अस्तित्व वाले कारपोरेट के तौर पर लघु कृषक कृषि-व्यवसाय परिसंघ का गठन किया गया जिसे भारतीय रिजर्ब बैंक, नाबार्ड और आई.डी.बी.आई. द्वारा वित्तपोषित किया गया। इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि अघु कृषक व्यवसाय संघ आर्थिक कार्यकुशलता, पर्यावरणीय अनुकूलता और सामाजिक सान्यता के सिद्वान्तों के आधार पर कार्य करेगा और 12 जिलों नामत: बारपेटा (असम); महबूब नगर (आंध्र प्रदेश); बलसाद (गुजरात); धारवाड़ (कर्नाटक); इर्नाकुलम (केरल); जबलपुर (मध्य प्रदेश); गंजम (उडीसा); पाण्डिचेरी; बीकानेर (राजस्थान); धर्मापुरी (तमिलुनाडु); पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश); और मिदनापुर (पश्चिम बंगाल), में शुरू होगा। लघु कृषक –व्यवसाय परिसंघ की कल्पना शासकीय तथा गैर-शासकीय संस्थाओं और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उघोगों में एक

नए परस्पर व सामाजिक समझौते को बढ़ावा देने के माध्यम से संसाधन हीन किसानों को आधुनिक कृषि-व्यवसाय के आर्थिक फायदे पहुंचाने की एक पद्वति के रुप में की गई है। एस.एस.ए.सी. की नीति में तिलहनोम,गन्ना, बागवानी, पशुपालन, रेशम उत्पादन के त्वरित विकास और बंजरभूमि विकास तथा प्रसंस्करण यानि फार्म उत्पादों की मूल्य वृद्वि की क्षमता पर जोर दिया जाता है। इस तरह, परियोजना का उद्देश्य पर्यावरणीय तौर पर सतत व सामाजिक तौर पर न्यासंगत तरीके से और साथ ही साथ लिंग संबंधी निष्पक्षता को जुनिश्चित करते हुए फार्म सेक्टर से तहरे लक्ष्यों- अधिक खाद्यन्न, अधिक रोजगार व अधिक आय, को प्राप्त करना है। परियोजना के तीन घटक होंगे, जैसे उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन। परियोजना एक ओर उत्पादन को बढ़ाने के अग्रवर्ती तथा पच्श्रगामी संबंध बनाए रखेगी तथा दूसरी ओर उत्पाद के बेहतर प्रसस्करण व विपणन संबंधी संबंध बनाएगी। इसे सहकारी क्षेत्र या संयुक्त उद्यम, जिसमें किसानों, सरकारी अधिकारियों और गैर –सरकारी संगठनों का प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, में कृषि उद्योग को स्थापित करके प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव हैं। किसानों में एस.एफ.ए.सी की धारणा से संबंधित जागरुकता लाने के उद्देश्य से कुछ राज्यों में जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाई गई हैं।

Relationship of energy input in agriculture and food production

2891. DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the standardised relationship of energy input in agriculture (horsepower per hectare) and food production;

(b) the development in Indian agriculture based on this parameter; and

(c) how does this situation compare with other countries?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) No standardised relationship between energy input in agriculture and food produciton, has been established, as increase in agricultural produciton depends on a large number of other factors, also, like use of irrigation water, seeds, fertilisers, plant protection measures, agro-climatic condtions, farm operations, etc. *(b)* anu *(c)* The tarm power availability in India has increased from 0.36 hp/ hectare in 1971 to 1.04 hp/hectare in 1994. No comparative studies with other countries have been made in this regard.

Production of foodgrains in State Farm Corporation of India

2892. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of production of foodgrains in State Farm Corporation of India at each of the farms situated in the States of Rajasthan, Haryana and Punjab during the last three years;

(b) how much expenditure was incurred on the purchase of fertilizers, agricultural implements, etc. during the period; and

(c) the names of the parties to whom the foodgrains were sold and the rate there of during the last three Year

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) State Farms Corporation of India (SFCI) Limited is mainly engaged in the production and sale of breeder, faundation and certified seeds of various crops like foodgrains, oilseeds, fibre crops etc. Details of production of seeds and foodgrains in SFCI at each of its farms situated in the States of Rajasthan, Haryana and Punjab during the last three years are given in the Statement *(See* below).

(b) and (c) Details of expenditure incurred on the purchase of fertilizers, agriculture: implements, etc. by these farms along with-the details of foodgrains sold by SFCI are enclosed as per Annexure *[See* appendix 180, Annexure No. 60]